



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India.

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31]

नई विल्सी, रविवार, फरवरी 17, 1980/माघ 28, 1901

No. 31]

NEW DELHI, SUNDAY, FEBRUARY 17, 1980/MAGHA 28, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न ही जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

प्रधिकारात्मक

नई विल्सी, 17 फरवरी, 1980

स्थानकांचि० ४०(प्र) — राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्धोषणा सर्वेमाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है —

यह: मेरा, भारत के राष्ट्रपति, नीलम संजीव रेही का समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें कि उड़ीसा राज्य का प्रामाण भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'संविधान' कहा गया है) के उपर्योग के प्रत्युमार महीने चलाया जा सकता है;

यह: प्रब्र. में, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त गवितयों का सथा उस निमित्त भुजे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी गवितयों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उद्धोषणा करता हूँ कि —

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल के निहित या एतद्वारा प्रयोक्तव्य सभी गवितयों, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने हाथ में लेता हूँ;

(ख) घोषित करता हूँ उक्त राज्य के विधान मंडल की गवितयों संसद के प्राधिकार द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होगीं; और

(ग) निम्नलिखित आनुचित्कारी और पारिणामिक उपर्योग करता हूँ जो इस उद्धोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिये मुझे आवश्यक या बाल्लभीय प्रतीत होते हैं; अर्थात् —

(i) इस उद्धोषणा के उपर्युक्त खंड (क) के आधार पर अपने हाथ में लिये गये हृत्यों और गवितयों का प्रयोग करते हैं, ऐसे लिये भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझूँ उक्त राज्य के राज्यपाल के साध्यम से कार्य करना विधिवूर्ण होगा;

(ii) उक्त राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपर्योगों के प्रश्वर्तन को एतद्वारा निष्पन्न किया जाता है, अर्थात् —

अनुच्छेद 3 के परन्तुका का उतना भाग जितने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंडल को निवेद करने से है;

अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध भारत के नियंत्रक महालेला परीक्षक द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है।

अनुच्छेद 163 और 164;

अनुच्छेद 166 के खंड (3) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य सरकार के कार्यों का मंत्रियों के द्वीच आवंटन से है; अनुच्छेद 167 और अनुच्छेद 169 के खंड (1) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प के पारित किये जाने से है;

अनुच्छेद 174 का खंड (1) और खंड (2) का उप-  
खंड (क); अनुच्छेद 175 से 178 तक (जिसमें  
ये दोनों सम्मिलित हैं); अनुच्छेद 179 का खंड (छ)  
और (ग) और उस अनुच्छेद का प्रथम परन्तुक और  
अनुच्छेद 180 और 181;

अनुच्छेद 186 का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के संवलमों और भत्तों से है; अनुच्छेद 188, 189, 193, 194, 195 और 196; अनुच्छेद 198; अनुच्छेद 199 का खंड (3) और खंड (4);  
अनुच्छेद 202 के खंड (3) का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के संवलमों और भत्तों से है, अनुच्छेद 208 से 211 तक (जिसमें यह दोनों सम्मिलित हैं); अनुच्छेद 213 के खंड (1) का परन्तुक और खंड (3) का परन्तुक; और  
अनुच्छेद 323 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध नापाल सहित रिपोर्ट को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखें जाने से है;

(iii) उक्त राज्य की विधान सभा एतद्वारा विधित की जाती है;

(iv) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निवेश का ग्राह्य उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निवेश लगाया जायगा और उसमें राज्य के विधान मंडल या विधान सभा के प्रति किसी निवेश का, जहाँ तक उसका संबंध उसके कृत्यों और उसकी गतिकोणों से है, ग्राह्य, जब तक कि संदर्भ में ग्रन्थाधीक्षित न हो, संसद के प्रति निवेश लगाया जायगा, और विधिष्ठतमा अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधान मंडल या विधान सभा के प्रति निवेश का ग्राह्य क्रमानुसार राष्ट्रपति और संसद या उसके सदनों के प्रति निवेश लगाया जायगा;

परन्तु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पेरा 1 से सेकंड पेरा 4 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं) के उपर्योगों पर प्रभाव नहीं ढालेगी और स राष्ट्रपति को इस खंड के उपर्योग (1) के प्रधीन उस सीमा तक जहाँ तक वह ठीक समझे, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी;

(v) संविधान में राज्य के विधान मंडल के या एतद्वारा बनाये गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निवेश का ऐसे ग्राह्य सामाया जायगा मानो उसके अन्तर्गत इस उद्घोषणा के भावार पर संसद द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपर्योग (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राविकारी द्वारा राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निवेश है, और उड़ीसा सांसदारप खंड अधिनियम, 1937 (उड़ीसा 1937 का अधिनियम 1) और सांसदारप खंड अधिनियम 1897 (1897 के 10वें) का उतना भाग जितना राज्य विधियों पर लागू है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के भारे में ऐसे प्रभावी होना मानो यह उस राज्य के विधान मंडल का अधिनियम है।

नई विल्ली;  
17 फरवरी, 1980

नीलम संजीव रेडी,  
राष्ट्रपति

[सं. V/11013/4/80-सी.एस.प्रार.]  
टी० सी० ए० श्रीनिवासबरदन, सचिव

नई विल्ली;  
17 फरवरी, 1980

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 1980

G.S.R. 40(E).—The following Proclamation by the President is published for general information :

Whereas, I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, am satisfied that a situation has arisen in which the Government of Orissa cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that—I

- (a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;
- (b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and
- (c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely :—
  - (i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;
  - (ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely :—
    - so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;
    - so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;
    - articles 163 and 164;
    - so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State; article 167 and so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;
    - clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of article 174; articles 175 to 178 (both inclusive); clauses (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article and articles 180 and 181;
    - so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 188, 189, 193, 194, 195 and 196; article 198; clauses (3) and (4) of article 199;
    - so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 208 to 211 (both inclusive); the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and
    - so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;
  - (iii) the Legislative Assembly of the State is hereby dissolved;
  - (iv) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses

thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the House thereof shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively :

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State ;

(v) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Orissa General Clauses Act, 1937 (Orissa Act 1 of 1937), and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

New Delhi; NEELAM SANJIVA REDDY,  
The 17th February, 1980. President.

[No. V/11013/4/80-CSR]

New Delhi; T. C. A. SRINIVASAVARADAN, Secy.  
The 17th February, 1980.

मार्केश  
नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1980

सांख्यिकी 41(म) -- राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित प्रादर्श संविधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :--

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्भूत मेरे द्वारा आज फरवरी, 1980 के 17वें दिन जारी की गई उद्घोषणा के बांध (ग) के उपब्रह्म (1) का अनुमत्य करते हुए मैं प्रतिवाचन निवेश करता हूँ कि उड़ीसा राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य मे प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल मे निहित या प्रयोक्तव्य गर्भी अस्तित्व, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के बांध (क) के आधार पर अपन हाथ मे ले लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निवेश और नियन्त्रण के अध्याधित रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

नई दिल्ली;  
17 फरवरी, 1980

नौसम नंजीव रेडी,  
राष्ट्रपति

[सं० वी/11013/4/80-स०एस०आर०]

नई दिल्ली;  
17 फरवरी, 1980

टी०सी०ए० ओनिवासवरदन, सचिव

## ORDER

New Delhi, the 17th February, 1980

**G.S.R. 41(E).**—The following Order by the President is published for general information :

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 17th day of February, 1980, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Orissa and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi; NEELAM SANJIVA REDDY,  
The 17th February, 1980. President.

[No. 11013/4/80-CSR]

New Delhi; T. C. A. SRINIVASAVARADAN, Secy.  
The 17th February, 1980.

